भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2013
दिनांक 31 जुलाई 2025

मिजोरम में तेल डिपो की स्थापना

†2013 श्री रिचर्ड वनलालह्लंगइहा:

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मिजोरम राज्य को तेल डिपो के अभाव के कारण समय-समय पर ईंधन की कमी का सामना करना पड़ रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने मिजोरम में तेल डिपो स्थापित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं;
(ग) यदि हाँ, तो प्रस्तावित स्थान, भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति और परियोजना के प्रारंभ और पूर्ण होने की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;
(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या केंद्र सरकार का राज्य सरकार के परामर्श से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का विचार है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने बताया है कि वर्तमान में मिज़ोरम राज्य में 115 खुदरा बिक्री केंद्र (आरओज) हैं। राज्य भर में निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा मौजूद है। इसमें टैंक ट्रकों का एक सुव्यवस्थित बेड़ा तथा पर्याप्त संभारतंत्रीय सहायता शामिल है। आरओज और ग्राहकों से प्राप्त अनुरोधों (मांग पत्रों) का शीघ्रता से निष्पादन किया जाता है। हालाँकि, कभी-कभी सड़क अवरोध आदि जैसी स्थानीय समस्याओं के कारण आपूर्ति की स्थिति प्रभावित होती है।

(ख) से (ङ) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने बताया है कि मिजोरम सरकार ने शुरुआत में बैराबी में भूमि की पेशकश की थी। हालांकि, आकलन के बाद, साइट को पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) डिपो के विकास के लिए अनुपयुक्त पाया गया। इसके बाद, सैरांग में एक वैकल्पिक साइट की पेशकश की गई। आकलन करने पर पाया गया कि प्रस्तावित साइट पहाड़ी इलाके, पर्याप्त ऊंचाई के अंतर और इसके भूकंप-संभावित क्षेत्र के कारण महत्वपूर्ण अभियांत्रिकी एवं संभारतंत्रीय चुनौतियां प्रस्तुत करती है। ये स्थानीय कारक बहुत हद तक अधिक परियोजना लागत में योगदान करते हैं। उपरोक्त कारकों के कारण प्रस्तावित स्थान पर सभी ओएमसीज की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की अपेक्षाकृत कम मांग को देखते हुए तथा बहुत अधिक परियोजना लागत के कारण इस स्थान पर पीओएल डिपो स्थापित करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

*****